यूपी के किसान बनेंगे उद्यमी और युवाओं को मिलेगा रोजगार, खाद्य प्रसंस्करण की 375 बड़ी इकाइयां होंगी स्थापित

योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है. साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले. इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयत्नशील है.

Written by - Zee Media Bureau | Edited by: Zee Media Bureau | Last Updated: Apr 30, 2022, 11:04 PM IST

लखनऊ: योगी सरकार किसानों को उद्यमी के तौर पर स्थापित करना चाहती है. इससे किसानों की आय तो बढ़ेगी ही, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 (संशोधित) की सहायता से 375 बड़ी इकाइयों की स्थापना की जाएगी. साथ ही पीएमएफएमई (PMFME) योजना के तहत 41,336 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जाएगी.

e-Shram Card धारकों को किस्त के अलावा भी मिल रहे हैं कई फायदे, जानें डिटेल्स

योगी सरकार का लक्ष्य

योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है. साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच साल में हर परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार का अवसर मिले. इसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयत्नशील है. सरकार चाहती है कि किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत मिले.

इसके लिए सरकार किसानों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़ेगी. खाद्य प्रसंस्करण के बाद फसल के खराब होने की आशंका नहीं रहेगी और बाजार में उत्पाद की अच्छी कीमत भी मिलेगी. इसके साथ ही कई रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे.

खुशखबरीः PM Kisan Yojana के लाभार्थियों को मिलेगा एक और लाभ, सरकार ने उठाया ये कदम

पीएमएफएमई योजना के तहत 41336 इकाइयां लगाई जाएंगी

सरकार पीएमएफएमई योजना के तहत 41336 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/उन्यन कराएगी. प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग (पीएमएफएमई) योजना के तहत खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करने के लिए सरकार सहायता देती है. इसके तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शुरू किए जा सकते हैं.

इसके साथ ही प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 (संशोधित) की सहायता से 375 बड़ी इकाइयों की स्थापना की जाएगी. इसके अलावा उद्यम लगाने के लिए किसानों और उद्यमियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगी. सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में 210000 उद्यमियों और किसानों को प्रशिक्षण दिलाने का है.